

20-21 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल :

मजदूर आन्दोलन में एक नई कल्प

देश की सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने केन्द्र व राज्य सरकारों की घोर मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 20-21 फरवरी को देश व्यापी हड़ताल का आयोजन किया। यह एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का व्यापक एकता का प्रदर्शन करते हुए सभी ट्रेड यूनियनों का एक मंच पर आना वक्त की जरूरत है। आज मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। मजदूर वर्ग के ज्यादातर लोग ठेकेदारी प्रथा के तहत बिना किन्हीं कानूनी अधिकारों के किसी तरह जिंदा रहने भर का वेतन पा रहे हैं। जो न्यूनतम वेतन हरियाणा व अन्य राज्य सरकारों ने घोषित किया है उसमें एक परिवार का पालन-पोषण तो दूर दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। मजदूरों के परिवार में बच्चे तक काम करने के लिये मजबूर होते हैं। श्रम कानूनों का तो बहुत से मजदूर नाम भी नहीं जानते। मशीनों पर काम करते वक्त अंग भंग हो जाने पर मजदूरों को भीख मांगने के लिये सड़कों पर धकेल दिया जाता है। करखानेदार मजदूरों से बिना किन्हीं सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक जगहों पर काम कराते हैं, जहां अंग-भंग होना या जान चली जाना आम बात है। घायल होने पर न तो समुचित मुआवजा मिलता है और न जान जाने पर। सालों-साल उच्च तकनीक की मशीनों पर काम करते हुए भी मजदूरों को परमानेंट नहीं किया जाता है। जब मजदूर इकट्ठा होकर संगठन या यूनियन बनाने की तरफ बढ़ते हैं तो ठेकेदार के गुंडे, बाउंसर, पुलिस सभी उनके ऊपर दुश्मनों की तरह टूट पड़ते हैं। श्रम विभाग तो पूरी तरह बेशर्मा होकर पूंजीपतियों का एजेन्ट बनकर रह गया है। ऐसे में मजदूरों की जिंदगी पूरी तरह पशुओं की तरह बनकर रह गयी है।

जो थोड़े बहुत मजदूर संगठित अथवा यूनियनीकृत हैं भी तो उनको मिलने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। श्रम अधिकारों में कटौती कर सरकार ने वास्तव में श्रम विभाग को भी प्रभावहीन बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

स्थायी मजदूरों की भर्ती पर अघोषित रोक लगी है इसलिये इन यूनियनों में मजदूरों की संख्या लगातार घट रही है।

आज संगठित यूनियनीकृत मजदूर अपने छिनते अधिकारों को चुपचाप देखते जा रहे हैं। कोई भी आंदोलन की हिम्मत करने का फैसला सीधे नौकरी को दांव पर लगाना हो चुका है।

जहां नए उद्योग लग रहे हैं वहां ज्यादातर मजदूर ठेकेदारी के तहत नियोजित किये जा रहे हैं। मजदूर जहां भी यूनियन बनाकर संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं वहीं दमन शुरू हो जाता है। मारुति सुजुकी मानेसर से लेकर सत्यम राकमैन (हरिद्वार) लखानी (फ़रीदाबाद) हर जगह मजदूरों को दमन उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं मिला है। अब सरकार ने अपनी मजदूर विरोधी नीतियों-निजीकरण-उदारोकरण वैश्वीकरण को और तेजी से आगे बढ़ाया है। बैंक से लेकर बीमा तक का निजीकरण कर सरकार इन्हें प्राइवेट हाथों-यानी पूंजीपतियों को सौंप रही है। ऐसे में सरकारी मजदूरों अथवा कर्मचारियों की नौकरियां व सुविधाएँ जहां दाव पर लगी हैं वहीं देश के करोड़ों लोग जो बैंक-बीमा में धन जमा करते हैं उनकी जीवन भर की कमाई मुनाफे की हवस में डूबे पूंजीपतियों व सटोरियों को मनमाफिक खेल खेलने के लिये सौंपी जा रही है। इस तरह देश, देशी-विदेशी पूंजीपतियों व सटोरियों की गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। इस से सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर-मेहनतकश जनता होगी। जिनकी जीवन भर की कमाई कभी भी सट्टाबाजार में उड़नछू हो जाएगी। और वे सड़क पर भूखों मरने को छोड़ दिए जायेंगे।

मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी आबादी असंगठित मजदूर तो आज भी 'श्रम कानूनों' के दायरे में नहीं आते। दिहाड़ी मजदूर, खेत मजदूर भवन निर्माण में लगे मजदूर, आंगनवाड़ी, भोजन माताये, आशा बहनें, निविदा पर सरकारी विभागों में लगे मजदूर आज भी श्रम कानूनों व सुविधाओं से आंशिक या पूरी तरह वंचित हैं।

एक तरह से मजदूर आज फिर उन्हीं कार्यपरिस्थितियों व अधिकार विहीनता की स्थिति में पहुंचाये जा रहे हैं जहां वे सौ-डेढ़ सौ साल पहले थे। मजदूरों की पिछली पीढ़ियों ने पूंजी के खिलाफ शानदार संघर्ष किए थे, कुर्बानियां दी थी



रोजी-रोटी की जगह लाठी गोली

जिसके बदौलत सरकार को मजदूरों को कुछ श्रम अधिकार व सुविधाएँ देनी पड़ी थी। लेकिन एक एक कर इन अधिकारों को गंवाकर मजदूर आज पूरी तरह अधिकार विहीनता की स्थिति में पहुंच गये हैं। आखिर यह स्थिति आई क्यों?

ऐसा इसलिये कि देश के शासक पूंजीपतिवर्ग ने मजदूर आन्दोलन को तोड़ने के लिये हर तरह के हथकंडे अपनाए। उसने मजदूर यूनियनों के भीतर अपने एजेन्ट तैयार किये। मजदूर आन्दोलन को कई ट्रेड यूनियनों ने तोड़ा। कहीं-कहीं तो पूंजीपतियों व मैनेजर्स ने मिलकर अपनी जेबी यूनियन खड़ी कर दी। मजदूर आन्दोलन में हड़ताल तोड़को को पाला पोषा। शासक वर्ग की सभी पार्टियों ने मजदूरों को अपने-अपने खेमों में विभाजित किया। मजदूरों को सबसे आगे बढ़े हिस्से को ज्यादा तनखाह व वेतन भत्ते बोनस, सुविधाएँ, विदेशी दौरे व सरकारी समितियों में शामिल कर उन्हें बाकी मजदूरों से काट दिया। मजदूर वर्ग में पूंजीपतियों व सरकार के दलालों ने मजदूरों को सिखाया कि सिर्फ अपनी कंपनी अपनी फैक्टरी व अपने वेतन के बारे में सोचो। उन्होंने मजदूर वर्ग की एक परिवार की चेतना की जगह हमारी

कंपनी एक परिवार की चेतना को बढ़ावा दिया। मजदूर वर्ग को उसके क्रांतिकारी विचारधारा व विरासत, विरत कर शासक वर्ग के नेताओं का पिछलग्गू बना दिया। कुल मिलाकर मजदूर वर्ग के भीतर दलाल नेताओं को पैदा करने के साथ मजदूर वर्ग के भीतर एक ऐसा सुविधा संपन्न तबका पैदा कर दिया जिसे अपने को मजदूर कहने में शर्म आने लगी। वह मानसिक तौर पर पूंजीपतियों व शासक वर्ग का गुलाम हो गया।

इसके साथ मजदूरों के भीतर स्थाई कैजुअल व ठेकेदारी मजदूरों का विभाजन कर एक फैक्टरी के भीतर भी मजदूरों को बांट डाला। स्थायी मजदूरों की स्थिति यह हो गई कि वे ठेकेदारी मजदूरों को लेबर कहने लगे, अपने को उनसे श्रेष्ठ समझने लगे, केवल अपने अधिकारों की ही चिंता करने लगे। ठेका मजदूरों को तो वे यूनियन का हिस्सा बनाने में भी हिचकने लगे।

रही सही कसर पूंजीवादी पार्टियों व जाति-संप्रदाय के संगठनों ने पूरी कर दी। इन्होंने भी मजदूरों को अपनी जाति, धर्म के आधार पर बांट डाला। सरकार व मजदूर आंदोलन में बैठे दलाल नेताओं ने मजदूरों को जहां केवल अपनी फैक्टरी

व सुविधाओं के बारे में सोचना सिखाया वहीं इन्होंने मजदूरों को बताया कि कानून ही सब कुछ है। जमीनी आंदोलनों की जगह श्रम न्यायालय व कोर्ट कचहरियों तक इन्होंने मजदूरों की लड़ाई को सीमित कर दिया। लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है, यह अब तक की कहानी है। लेकिन तस्वीर बदल भी रही है। मजदूर वर्ग को लंबे समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता। मजदूर आज एक बार फिर संघर्ष की ओर मुड़ रहे हैं। मजदूर वर्ग की एकता एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पूंजीपतियों व सरकार की नींदे मजदूर आंदोलन के इस बढ़ते उभार से हराम है। देश के कोने-कोने में मजदूर वर्ग के जुझारू संघर्ष फूट रहे हैं। दलाल नेताओं व यूनियनों से अपना पिंड छुड़ाकर मजदूर अपनी स्वतंत्र यूनियन खड़ी कर रहे हैं।

विगत समय में मारुति सुजुकी मानेसर गुड़गांव से लेकर हुंडई (मद्रास) व बंगाल के जूट मजदूरों विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के मजदूरों ने अपनी जुझारू एकता का प्रदर्शन कर सरकार व प्रशासन का लोहे के चने चबाने को मजबूर कर दिया। मारुति सुजुकी के मजदूरों ने स्थायी ठेका ट्रेनी सहित सभी मजदूरों की जुझारू एकता का एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। मजदूर वर्ग के देश भर में होने वाले बिखरे व छिटपुट संघर्षों का ही परिणाम है कि केन्द्रीय हेड यूनियन राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आवाहन किया है।

आज सरकार व पूंजीपति वर्ग मजदूरों पर चौतरफा हमला कर रहा है। दिहाड़ी, ठेका मजदूर से लेकर सरकारी कर्मचारी सभी पूंजीपति वर्ग व सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं। प्रतिरोध की आवाजों को भयंकर दमन के बल पर कुचला जा रहा है। ऐसे में मजदूर वर्ग को एकजुट होकर पूंजीपति वर्ग को चुनौती देनी ही होगी। इस देश के 25 करोड़ से अधिक मजदूर व 45 करोड़ मेहनतकश अगर जागृत हो जायें तो पूंजीपति वर्ग को निश्चित तौर पर पीछे हटना पड़ेगा। मजदूर वर्ग को उसे, सत्ता की चुनौती देनी ही होगी। पूंजी के राज को समाप्त कर, मजदूर मालिक के रिश्तों का खात्मा करके, मजदूर राज (समाजवाद) की स्थापना कर मजदूरों की मुक्ति संभव है।

-नागेन्द्र मनराल

स्थाईकरण मांगोगे तो शोवा में मजदूर नहीं रह पाओगे

फरीदाबाद, सेक्टर 58 प्लॉट नं. 23-32 स्थित शोवा इंडिया प्रा.लि. के मजदूर स्थायीकरण, वेतनवृद्धि व अन्य श्रमिक अधिकारों के लिये संघर्षरत हैं। मजदूरों द्वारा कंपनी के भीतर संगठित होने की भनक लगने के साथ प्रबंधन उत्पीड़न पर उतर आया। 5 फरवरी को कंपनी में 3 जिप्सी पुलिस व बाउंसर मंगाकर प्रबंधन ने दो नेतृत्वकारी मजदूरों विरजन बघेल व सुरेश कुमार को ठेकेदार मनोज शर्मा द्वारा बुलाकर इस्तीफा लिखने को कहा। इस मामले की भनक जैसे ही बाकी मजदूरों को लगी वे सभी इकट्ठा हो गये और इसका विरोध किया। मजदूर फैक्टरी के अंदर ही धरने पर बैठ गए इस पर ठेकेदार ने सभी मजदूरों से इस्तीफा देने को कहा। तथा कंपनी से बाहर निकलने के लिये दबाव डाला। मजदूरों के प्रतिरोध करने पर पुलिस ने बलपूर्वक मजदूरों को कंपनी से 100 मीटर दूर बैठने को कहा। मजदूर इसके बावजूद गेट के सामने बैठकर अपना

आंदोलन जारी रखे हुए हैं। फिलहाल कंपनी ने मजदूरों को फैक्टरी के बाहर 100 मीटर के दायरे से बाहर रखने के लिये स्टे के लिये आवेदन किया था जो 12 फरवरी को खारिज हो गया।

शोवा जापानी मूल की कंपनी है। यह कंपनी चौपहिया वाहनों के लिये स्टीयरिंग तथा दुपहिया वाहनों के शॉकर बनाती है। कंपनी में तीन लाइनों के अंतर्गत सभी काम प्रबंधकों व सुपरवाइजर्स के अधीन होता है लेकिन तनखाह बांटने का काम दो ठेकेदारों के माध्यम से होता है।

ज्यादातर मजदूर हाईस्कूल व आई टी. आई. पास हैं कुछ मजदूर डिप्लोमाधारी भी हैं। ज्यादातर मजदूरों को काम करते हुए 5-6 साल से ऊपर हो गया है लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। मजदूरों का ई.पी. एफ. कटता है लेकिन उसकी रसीद नहीं दी जाती और नंबर तक नहीं बताया जाता है। कुशल व शिक्षित प्रशिक्षित मजदूर होने के बावजूद इन मजदूरों की तनखाह 5 हजार से साढ़े सात

शोवा कंपनी के मजदूर स्थायीकरण, श्रम अधिकारों, निकाले मजदूरों की वापसी व महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि के लिये संघर्षरत हैं। अभी तक श्रम विभाग के अधिकारियों ने इनकी सुध नहीं ली है। प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर 12 तारीख को एक विपक्षीय वार्ता की बात कही थी जो कि नहीं हो पायी क्योंकि इसी दिन मजदूरों को कोर्ट में मालिक द्वारा दायर स्टे आवेदन के संबंध में अपना पक्ष रखना था।

हजार के बीच है। ओवर टाइम के मामले में कंपनी जालसाजी की हद कर देती है। मजदूरों को ओवर टाइम सिंगल रेट से दिया जाता है लेकिन दिखाया डबल रेट से है। इसके लिये 100 घंटे ओवर टाइम कराने पर उसे 50 घंटे दिखाकर दुगुनी दर

से भुगतान का दिखावा किया जाता है। कंपनी में अभी तक एक भी मजदूर स्थायी नहीं है। सभी मजदूर ठेकेदार मनोज शर्मा व मुकेश कौशिक के आदमी दर्शाये जाते हैं। कंपनी में अभी 150 मजदूर लगभग काम करते हैं। दिसम्बर 2011 में कंपनी ने 250 मजदूरों की छंटनी कर दी। इन मजदूरों से कहा गया था कि दो पहिया (टू व्हीलर) का प्लॉट लगाने पर उन्हें वापस बुला लिया जायेगा लेकिन टू व्हीलर प्लॉट लगने पर नए मजदूरों की भर्ती की गयी। पुराने मजदूरों को वापस नहीं बुलाया गया। 2011 में मंदा के दौरान मजदूरों को 20 से 30 दिनों के लिए घर भेज दिया गया उन्हें इस दौरान का कोई वेतन नहीं दिया गया जबकि स्टाफ को इस दौरान पूरा वेतन दिया गया। मजदूरों को वापस बुलवाने के बाद उनसे इंटे पथड व रोड़े ढुलवाये गए, इससे मजदूर खुद काम छोड़कर चले गये।

मजदूरों के अनुसार इस कंपनी में मैनेजर्स व सुपरवाइजर्स का मजदूरों के साथ व्यवहार अत्यंत क्रूर व अमानवीय

रहा है। कंपनी प्रबंधन ने छः वर्ष से कंपनी में कार्यरत विजय कुमार को धक्के मारकर निकाल दिया। सुपरवाइजर विनीत त्यागी मजदूरों से गाली गलौज करता है तथा उसने एक बार एक बुजुर्ग मजदूर राजकुमार को चप्पल फेंककर मारी।

शोवा कंपनी के मजदूर स्थायीकरण, श्रम अधिकारों, निकाले मजदूरों की वापसी व महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि के लिये संघर्षरत हैं। अभी तक श्रम विभाग के अधिकारियों ने इनकी सुध नहीं ली है। प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर 12 तारीख को एक विपक्षीय वार्ता की बात कही थी जो कि नहीं हो पायी क्योंकि इसी दिन मजदूरों को कोर्ट में मालिक द्वारा दायर स्टे आवेदन के संबंध में अपना पक्ष रखना था। 13 फरवरी को फिर वार्ता रखी गयी है। फिलहाल मजदूर संघर्ष में डटे हैं उनका कहना है कि अगर शीघ्र उनकी मांगों का हल नहीं निकाला गया तो वे उग्र कदम उठाने को बाध्य होंगे।

-नागेन्द्र मनराल